और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाने का विचार है ?"

श्री सभापति : रूस इसमें कहां आ गया ?"

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यूगोस्लाविया और मिश्र के व्यापार में क्यों कमी आई यह मैं बता रहा हूं। चूंकि रूस से जो सौदा यह सरकार करती है उसमें ज्यादा देती है बनिस्बत मिश्र के, बनिस्बत यूगोस्लाविया के, बनिस्बत, अन्य मुल्कों के। इसलिए इन मुल्कों ने सौदा कम करना शुरु कर दिया है क्योंकि रूस के साथ इस सरकार ने ऐसे समझौते किए हैं।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Sir, this question was raised also the other day on the floor of the House and my colleague answered it very clearly that it would not be correct to suggest that the price that we get for our exports to East European countries including Russia is less than what we can get from elsewhere. On the contrary figures indicate in respect of certain items what we have got is more favourable. So far as Yugoslavia is concerned it is true that for some of the export and import items—that is, export to and import from—prices are being renegotiated because of the higher cost of production both at this end and also at that end.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ।

MR. CHAIRMAN: He has suggested a reason; is that reason correct or not? What do you want to say about it?

श्री राजनारायण : रूस के साथ माननीय मंत्री जी ने केवल निर्यात के बारे में बताया है, लेकिन वाणिज्य में तो निर्यात और आयात, दोनों शामिल हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्यात के बारे में मंत्री जी ने बता दिया, अब वे कृपा कर के आयात के बारे में बतायें कि हम रूस से जो सामग्री मंगाते हैं और वही सामग्री अगर दूसरे मुल्कों से मंगाते हैं तो रूस को उस के लिए हम को ज्यादा दाम देना पड़ता है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के, क्या यह सही है ? और जो समझौते हुए हैं क्या उन को आप मेज पर रखेंगे ?

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइये।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: In what I have said about East European countries, including Russia, I have referred to both export and import. Since this is a specific question about Yugoslavia, I concentrated more on Yugoslavia. I have said that our prices for the export of wagons, for instance, and import of ships have been re-negotiated because of the higher cost of production.

SHRI A. G. KULKARNI: We have bilateral trade with Egypt and Yugoslavia. In regard to Egypt and the Sudan difficulty comes in because we sell them at a fixed price; while these countries sell their commodities to India at prices based on world tender. Thereby this country loses the chance of getting a better price. May I know whether the Government will enquire* into this in the case of Egypt and the Sudan and take appropriate steps so that our country's interests are not harmed?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Steps have alrendy been taken to ensure that our interests are not harmed.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि इजिप्ट से जो लांग स्टैपिल काटन इंपोर्ट की जाती है वह इस लिए होती है कि उस का कपड़ा मुल्क में बना कर एक्सपोर्ट किया जाय ताकि ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमाया जा सके। तो मैं जानना चाहती हूं कि हम कितना कपड़ा बना कर उस रुई का यहां से बाहर भेज रहे हैं ?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Most of the textile produced out of the long-staple cotton imported from outside is meant for home consumption.

MR. CHAIRMAN: Next question.

पाकिस्तान की ओर पावना

*271. **श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी** :†
श्री सुब्रमण्यम स्वामी :
सरदार कुमार सं० चं० आंग्रे :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भैरों सिंह शेखावत :

क्या वाणिज्य मंत्री 19 मार्च, 1974 को

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri O. P. Tyagi.

राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1028 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाजन के समय पाकिस्तान के साथ किये गये वित्तीय करारों के अधीन पाकिस्तान की ओर से भारत का कितना पावना बाकी है और उस ऋण पर आज तक कुल कितना ब्याज चढ़ गया है जो भारत को मिलना है ।

†[Amount due from Pakistan

•271. SHRI O. P. TYAGI: SHRI S. C. ANGRE: SHRI SUBRAMANIAM SWAMY:
SHRI PRAKASH VIR SHASTRI: SHRI B. S. SHEKHAWAT:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1028 given in the Rajya Sabha on the 19th March, 1974 and state the amount of loan Pakistan owes to India under the financial agreements entered into with that country at the time of partition and the total interest which has accrued to India in respect of this loan upto date?]

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN): Pakistan's partition debt to India is of the order of Rs. 300 crores; the precise amount has not so far been agreed upon despite efforts made on various occasions. Under the partition arrangements concluded in December 1947 this debt was repayable by Pakistan in Indian rupees in 50 annual equated instalments of principal and interest (at 2$ per cent per annum) commencing from the 15th August, 1952. In the absence of any payment by Pakistan towards repayment of principal or interest, the accumulated interest at the normal rate (2J per cent) would by now be nearly equal to the amount of the debt due from Pakistan.

‡[**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : पाकिस्तान पर भारत का विभाजन ऋण 300 करोड़ रुपये के लगभग है लेकिन बहुत से मौकों पर की गयी अनेक कोशिशों के बावजूद इस ऋण की ठीक-ठीक रकम के बारे में सहमति नहीं हो सकी है । दिसम्बर 1947 में तय की गयी विभाजन व्यवस्था के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा इस ऋण का मूलधन और ब्याज ($2\frac{7}{8}$ प्रतिशत की दर से) 15 अगस्त 1952 से बराबर-बराबर की 50 किश्तों में भारतीय रुपये में लौटाया जाना था । लेकिन पाकिस्तान ने मूलधन और ब्याज की कोई भी किश्त नहीं अदा की है इसलिए इस समय तक सामान्य दर ($2\frac{7}{8}$ प्रतिशत) पर इकट्ठा होने वाला ब्याज की रकम पाकिस्तान द्वारा लौटाये जाने वाले ऋण की रकम के लगभग बराबर हो गयी है ।]

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने इस बात की ओर संकेत किया कि 300 करोड़ के लगभग धन और उतना ही करीब ब्याज हो गया है और यह भी उन्होंने बताया कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई इंस्टालमेंट नहीं दिया । 50 इंस्टालमेंट की बात थी । तो इस से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान इस धन को, इस ऋण को चुकाने के मूड में नहीं है और हमारी गवर्नमेंट में भी शब्द तो हिन्दी शब्दकोश में कोई दूसरा नहीं है . . .

श्री राजनारायण मैं दूसरा शब्द बतला दूंगा ।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : नपुंसकता के लिए क्या है ?

श्री राजनारायण : नपुंसकता तो हिन्दी है ही । हिजड़ा कह दीजिए ।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी :सभा पति महोदय, हमारी सरकार की स्थिति बड़ी दयनीय है अपना कर्ज लेने के लिए । मैं जानना चाहूंगा कि इस कर्जे को इंस्टालमेंट में लेने की दृष्टि से कितनी बार आजादी के पश्चात् भिन्न-भिन्न अवसरों पर समझौते हुए हैं और कितनी बार आपने प्रयत्न किया है और उसका पाकिस्तान ने क्या उत्तर दिया

†[ ] English translation.
†[ ] Hindi translation.

है? यदि वह मूड में नहीं है तो इस धन को वसूल करने के लिए आप क्या उपाय बरतने जा रहे हैं? राइट-आफ करेंगे या कोई उपाय इस्तेमाल करेंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN: The later discussions that were held with the Pakistani representatives were in 1959-60. After that, as all Members know, in the last whole decade the relations had been somewhat strained and no further talks have been held. This is the position where the whole matter stands now.

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मैंने यह पूछा था कि क्योंकि उसके मूड से साफ जाहिर है कि वह मना करता है तो क्या आप भविष्य में कोई विचार इस रुपये को शामिल करने का रखते हैं, यदि हां तो वह क्या है ?

श्री य० ब० चव्हाण : बातचीत करना ही तरीका है । इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मैं दूसरा प्रश्न यह करना चाहता हूं कि गत युद्ध यानी 1971 के युद्ध में जो पाकिस्तान के सिपाही यहां रखे गए उनके रख-रखाव पर और उनकी सेलेरी आदि पर जो आपका खर्च हुआ है ?—यह तो अभी निकट भविष्य में हुआ ही है—इसकी वसूली के लिए शिमला एग्रीमेंट हुआ, दिल्ली में बातचीत हुई, तो इन सब अवसरों पर यह जो धन आपका खर्च हुआ है इसके वसूल करने के लिए भी पाकिस्तान के सामने आपने कोई बात रखी है? यदि हां तो पाकिस्तान का क्या उत्तर मिला?

SHRI V. B. CHAVAN: I will need notice for this question.

MR. CHAIRMAN: He needs a separate notice. The question really does not arise out of this. But he wants notice for that.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि 1965 में जो हमारे जहाज पकड़े गए थे जिनके ऊपर कुछ सामान भी लदा हुआ था, व्यापारिक सामान, तो उसके लिए सरकार ने प्रयास भी किया और बाद में भी कई वर्षों तक यह चर्चा चलती रही कि वह सामान वापस हो जाए, जहाज वापस हो जाए या उनके धन का भुगतान हो जाए तो उस संबंध में पाकिस्तान की क्या कोई अनुकूल प्रतिक्रिया थी? यदि नहीं तो भविष्य में उस धन और सामान को न मिलने का सोच कर, छोड़ दिया ?

श्री य० ब० चव्हाण : पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, आपके सवाल का जवाब पहले दिया जा चुका है । अब सवाल पूछते तो हमें पहले इंटिमेशन चाहिए ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : क्या यह सही है कि सरकार ने अभी 1971 के युद्ध के पश्चात् बार-बार इस बात का प्रयत्न किया है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच जितने भी डिसप्यूट किस्म के मैटर्स हैं उनका कार्डियल सैटलमेंट हो जाए ? सरकार से मैं जानना चाहूंगा कि इन डिसप्यूटिड मैटर्स में 300 करोड़ रुपये की अदायगी का भी प्रश्न है ?

श्री य० ब० चव्हाण : मैंने कोशिश की सुनने की, मैं सुन नहीं पाया ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैंने यह पूछा था कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में जितने भी डिसप्यूटिड मैटर्स हैं उन डिसप्यूटिड मैटर्स की लिस्ट में 300 करोड़ रुपये की अदायगी का मामला भी शामिल है या नहीं ?

SHRI Y. B. CHAVAN: There is no question of having a consolidated list of the disputes. But it is a fact that this amount which they owe us we are showing it in every Budget; even in this year, if you refer to a certain page in the Explanatory Memorandum, it is mentioned there. Naturally it is a thing that they owe us, which is not settled. Therefore, it is one of the unsettled questions.

श्री भैरों सिंह शेखावत : मेरा कवेश्चन यह नहीं है । मेरा कवेश्चन यह है कि जितने आपके डिसप्यूटिड मैटर्स हैं उनकी लिस्ट में इस प्रश्न को शामिल किया गया है या नहीं कि पाकिस्तान से

हमें 300 करोड़ रुपये की रकम वसूल करनी है ?

श्री य० ब० चव्हाण : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनसैटल्ड मैटर्स है और हमारे रिकार्ड में है ।

श्री श्याम लाल यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो पिछला युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान के दो हिस्से हुए-बंगला देश और पाकिस्तान--तो इसमें जो खर्च हुआ उस को दौनों देशों में वितरित किया गया या केवल पाकिस्तान के ऊपर है डाला गया जब सरकार यह देख रही है कि इतने दिनों तक यह धन किसी भी प्रकार से वसूल नहीं हो रहा और न इस संबंध में वार्ता हो सकी तो दोनों देशों के बीच जिस प्रकार के मधुर सबंध कायम किये जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार यह सोचती है कि इसको राइट-आफ कर दिया जाए ?

SHRI Y. B. CHAVAN: The hon. Member is making certain suggestions. I do not think I should express an opinion on that.

श्री राजनारायण : क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव : मेरा पहला सवाल था कि बंगला देश और पाकिस्तान के बीच इस धन के बारे में क्या कोई बंटवारा हुआ है या केवल पाकिस्तान पर यह रखे हैं और दूसरा क्या आपका विचार है बताएं . . .

श्री य० ब० चव्हाण : उनके साथ समझौते से तो बंगलादेश बना नहीं था । तो क्या बंगलादेश को मान्यता नहीं दें ?

श्री राजनारायण : श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न है । देखिए, श्याम लाल जी का सीधा प्रश्न है ।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

12 NOON

श्री राजनारायण : क्वेश्चन आवर से हमारा संबंध नहीं है, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति : वह पहले सवाल का जवाब आ गया ।

श्री राजनारायण : सवाल यह है कि 300 करोड़ रु० जो मंत्री जी ने कहा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, तो वह 300 करोड़ रु० मंत्री जी की किताब में किसके पास लिखा हुआ है, पाकिस्तान के नाम लिखा हुआ है या . .

श्री सभापति : उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री राजनारायण : कहां जवाब दे दिया श्रीमन् ?

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

S.T.C. policy on import of books

*272. SHRI DHARAMCHAND JAIN: SHRI ROSHANLAL: SHRI SARDAR AMJAD ALI: SHRI C. P. MAJHI:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation has changed its policy regarding import of books;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether it has caused any adverse impact on indigenous book market?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI AC. GEORGE): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Foreign Exchange earned through public and private sector hotels

*273. SHRI M. S. ABDUL KHADER: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange earned by public and private sector hotel during the last three years, year-wise; and

(b) what measures Government have taken to check leakage and increase earning of foreign exchange from this source?